

January 17, 2026

Inauguration of Handicraft Expo Jodhpur at Trade Facilitation Centre.



Handicraft Expo Jodhpur was launched at Trade Facilitation Centre by Union Minister, Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat, who was the chief guest. Present also was Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel who was also the Minister of Law and Legal Affairs. Addressing the event held by The Export Promotion Council on Handicraft, Shekhawat emphasised the fact that the Indian craft of woodwork and colour as well as thousands of years old civilisation is a living memory of India. He mentioned that such places as the Handicraft Expo Jodhpur help to retain cultural heritage and show it to the world level. He also attributed handicrafts to creative economy, creation of jobs, decentralisation of economy and clearing of the rural urban divide.

The main highlights of the Minister speech:-

- The traditions of Indian craft were referred as a living cultural identity, which was developed through centuries.
- Handicrafts were introduced as intergenerational creativity, rather than as skill, as a cultural awareness.
- It was reported that the handicraft industry was getting a better footing in the creative economy.
- An alternative to the limited-style arts that prevailed elsewhere was to focus on Indian handicrafts as a variety of crafts that were competitive across the globe.

- The industry was associated with decentralisation of the economy and decreasing the rural-urban distance.
- It was indicated that handicrafts were one of the areas that offered very high employment opportunities in the nation.
- The message of changing the name of the organization to local to global was repeated under the leadership of PM Narendra Modi.
- It was reported that the government was in support of trade and industry through thick and thin, as the world experienced economic hardships and that they had a partnership strategy of helping the artisans and entrepreneurs in having a better life.

The importance of this to RAS prelims and mains :-

- Art & Culture + Heritage conservation: The Living traditions and cultural identity: Handicrafts.
- Tourism and branding of destinations: Incidents that enhance the cultural presence of Rajasthan.
- Economy and employment: The handicrafts as a potential inclusion, employment-intensive, decentralised sector.
- Governance style: Government industry relationship to dignified lives and market entry.

Objectives and benefits

Objectives

- Offer the Indian crafts a broader platform at the Handicraft Expo Jodhpur.
- Enhance conservation and marketing of cultural heritage using organised events.
- Support livelihoods: This is done by linking the artisans and entrepreneurs to broader opportunities.

Benefits

Increases the presence of the varied handicrafts in the creative economy in India.

Expresses an artisan-grounded sector to support employment and inclusion.

Promotes the change of local promotion to global competitiveness using market-based platforms.

Conclusion

The Handicraft Expo Jodhpur demonstrates the potential to support each other between cultural heritage and economic opportunity. Having projected India as a living identity through her craft traditions and their connection with jobs, decentralisation, and global competitiveness, the event reiterates the applicability of

the handicraft to the culture, tourism and inclusive growth- areas of RAS preparation concern.

MCQs (RAS Prelims pattern)

Q1. What was the venue of the Handicraft Expo Jodhpur where the news was launched?

- a) Jawahar Kala Kendra, Jaipur
- b) Trade Facilitation Centre
- c) Palace of Umaid Bhawan, Jodhpur.
- d) Jaipur, Rajasthan International Centre.

Answer: b

Explanation : The report informs that the expo was arranged and opened at the Trade Facilitation Centre, which is why option (b) is right.

Q2. As the address of the Union Minister shows, the handicraft industry is a contributor to which of the following?

- a) Luxury consumption (only) and urban markets.
- b) Economic decentralisation and opening the rural-urban divide.
- c) Minimising cultural difference through homogenising art.
- d) Raising the number of specialised artists to a very small number on employment.

Answer: b

Rationalisation: The minister associated handicraft with economic decentralisation, assisting the urban-rural gap, and also put a lot of emphasis on its high employment potential.

Q3. What was the slogan pair that was applied when defining the direction of India in terms of promoting local products and international exposure?

- a) Make in India and Digital India.
- b) Startup India and Standup India.
- c) Vocal: Local and Local: Global.
- d) Swachh Bharat and Jal Jeevan Mission.

Answer: c

Explanation The speech clearly states that India is marching with the slogan of Vocal for Local and Local for Global and hence the right choice is to go with option (c).

ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर का उद्घाटन।

ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (विधि एवं विधिक कार्य मंत्री भी) भी उपस्थित रहे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि भारतीय शिल्प परंपराएँ—वैशिकर काष्ठ एवं रंग कला—हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की जीवंत पहचान हैं। उन्होंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर जैसे आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे वैशिक मंच तक पहुँचाने में मदद करते हैं। उन्होंने हस्तशिल्प को क्रिएटिव इकोनॉमी, रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने से भी जोड़ा।

मंत्री के भाषण के प्रमुख बिंदु

- भारतीय शिल्प परंपराओं को सदियों में विकसित हुई “जीवंत सांस्कृतिक पहचान” बताया गया।
- हस्तशिल्प को केवल कौशल नहीं, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित “रचनात्मकता” और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- यह कहा गया कि क्रिएटिव इकोनॉमी में हस्तशिल्प उद्योग को नई और मजबूत पहचान मिल रही है।
- अन्य देशों की सीमित शैलियों की तुलना में भारतीय हस्तशिल्प को विविधतापूर्ण और वैशिक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बताया गया।
- उद्योग को अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण-शहरी दूरी कम करने से जोड़ा गया।
- यह संकेत दिया गया कि हस्तशिल्प देश में बहुत अधिक रोजगार अवसर देने वाले क्षेत्रों में शामिल है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “वोकल फॉर लोकल” से “लोकल फॉर ग्लोबल” की दिशा को दोहराया गया।
- वैशिक आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार के व्यापार और उद्योग के साथ मजबूती से खड़े रहने तथा कारीगरों और उद्यमियों के लिए बेहतर जीवन-स्तर हेतु साझेदारी-आधारित रणनीति अपनाने की बात कही गई।

RAS प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व

- कला एवं संस्कृति + धरोहर संरक्षण: हस्तशिल्प को “जीवंत परंपरा” और सांस्कृतिक पहचान के रूप में समझना।

- पर्यटन और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग: ऐसे आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक उपस्थिति और आकर्षण बढ़ाते हैं।
- अर्थव्यवस्था और रोजगार: हस्तशिल्प एक समावेशी, रोजगार-प्रधान और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के रूप में उभरता है।
- शासन शैली: सरकार-उद्योग साझेदारी, सम्मानजनक आजीविका और बाजार तक पहुँच के दृष्टिकोण से प्रासंगिक।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर के माध्यम से भारतीय शिल्पों को व्यापक मंच प्रदान करना।
- संगठित आयोजनों के जरिए सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार को मजबूत करना।
- कारीगरों और उद्यमियों को व्यापक अवसरों से जोड़कर आजीविका समर्थन देना।

लाभ

- क्रिएटिव इकोनॉमी में विविध भारतीय हस्तशिल्प की उपस्थिति बढ़ती है।
- कारीगर-आधारित क्षेत्र को मजबूती देकर रोजगार और समावेशन को समर्थन मिलता है।
- बाजार-आधारित मंचों के जरिए स्थानीय उत्पादों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर यह दिखाता है कि सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक अवसर एक-दूसरे को कैसे सशक्त कर सकते हैं। भारतीय हस्तशिल्प परंपराओं को जीवंत पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हुए, इसे रोजगार, विकेंद्रीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ना—संस्कृति, पर्यटन और समावेशी विकास जैसे RAS के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

Q1. समाचार के अनुसार हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ?

- जवाहर कला केंद्र, जयपुर
- ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर
- उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर
- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर

उत्तर: b

रिपोर्ट के अनुसार एक्सपो का आयोजन और उद्घाटन ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में हुआ, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q2. केंद्रीय मंत्री के संबोधन के अनुसार हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख योगदान किसमें बताया गया?

- केवल लगज़री उपभोग और शहरी बाजारों में

- b) आर्थिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने में
- c) कला रूपों का एकरूपीकरण कर सांस्कृतिक विविधता घटाने में
- d) रोजगार को बहुत सीमित विशेष कलाकारों तक सीमित करने में

उत्तर: b

मंत्री ने हस्तशिल्प को आर्थिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण-शहरी अंतर कम करने और उच्च रोजगार क्षमता से जोड़ा, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q3. स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर वैश्विक पहुंच की दिशा बताने के लिए कौन-सा नारा-युग्म उपयोग किया गया?

- a) मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया
- b) स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया
- c) वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल
- d) स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन

उत्तर: c

भाषण में स्पष्ट रूप से “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल फॉर ग्लोबल” का उल्लेख किया गया है, इसलिए विकल्प (c) सही है।

120 parliamentary delegates of 40 Commonwealth countries to visit Jaipur (17-18 January)



On 17 and 18 January, a group of 120 members of parliament of 40 Commonwealth countries will remain at Jaipur. The group consists of Presiding Officers (Speakers/Chairpersons), legislature members and senior officials in parliament of Commonwealth countries. Rajasthan Legislative Assembly Speaker Vasudev

Devnani will receive the delegates at Jaipur Airport on Saturday morning. The Commonwealth parliamentary delegates will be learning the parliamentary working regime and parliamentary traditions of the state during the two-day programme. They will also pay visits to major historical places in order to learn the culture of Rajasthan that will enable governance outreach to be attached with cultural diplomacy and exposure to tourism.

Key programme details

- The delegates of the Commonwealth parliament will be spending two days (17-18 January) in Jaipur.
- The delegation is a representation of 40 Commonwealth countries and it is 120 members.
- The delegation will be presented to assembly Speaker Vasudev Devnani in Jaipur Airport on Saturday morning.
- The tour will involve an introduction to the parliament system and state traditions of work.
- On the first day, the delegates will be visiting Amer Fort, Hawa Mahal, City Palace and Albert Hall.
- In the afternoon, the delegation will be visited by the Constitutional Club after the heritage visits.
- Naveen Jain, Principal Secretary, General Administration Department, reviewed preparations at the Secretariat and gave orders that arrangements be kept tight and inter-departmental coordination of preparations be maintained.

Objectives and benefits

Objectives

- Arrange educational activities on parliamentary processes and customs to the visiting parliament.
- Exhibit the heritage and cultural attractions of Jaipur in the two-day program.
- Make sure that the logistics of the visit of the Commonwealth parliamentary delegates proceeds without any complications through the interdepartmental coordination.

Benefits

- Enhances institutional interaction and exposure of parliament between Rajasthan and Commonwealth legislatures.
- Improves the visibility of Jaipur by taking a synergistic approach to the exposure of governance and tourist attraction of culture.
- Shows ability in administration by making arrangements of a top level international delegation.

Conclusion

The visit undertaken by 120 parliamentary representatives of 40 Commonwealth countries to the Jaipur is a parliamentary exposure as well as a heritage outreach. The programme brings out the governance practices and cultural prowess of Rajasthan by connecting the study of traditions in the parliament and tourism of key historical sites. The preparatory review which is headed by the General Administration Department highlights the role of coordination in the management of high profile international visits.

MCQs (RAS Prelims pattern)

Q1. The party of delegation which visited Jaipur on 17-18 January includes:

- a) 100 delegates from 50 countries
- b) 120 representatives of 40 Commonwealth countries.
- c) 140 representatives of the 35 Commonwealth countries.
- d) 80 delegates from 40 countries

Answer: b

Explanation: According to the news 120 parliamentary delegates of 40 Commonwealth countries will visit Jaipur on 17 and 18 January.

Q2. Who will be the welcoming party to the Commonwealth parliamentary delegates at Jaipur Airport?

- a) Rajasthan Chief Secretary.
- b) Governor of Rajasthan
- c) Vasudev Devnani, the speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.
- d) Rajasthan Chief Minister.

Answer: c

Explanation: Assembly Speaker Vasudev Devnani will receive the delegation at Jaipur Airport in the morning on Saturday.

Q3. What were the places that the delegates will visit on the first day of their heritage tour of Jaipur?

- a) Nahargarh Fort, Jal Mahal, Jantar Mantar, Birla Mandir.
- b) Amer Fort, Hawa Mahal, City Palace, Albert Hall.

- c) Amer Fort, Jantar Mantar, Jal Mahal, Albert Hall.
- d) Birla Mandir, City Palace, Nahargarh Fort, Hawa Mahal.

Answer: b

Description: The first day is to visit Amer Fort, Hawa Mahal, City Palace, and Albert Hall and visit the Constitutional Club in the afternoon.

40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 संसदीय प्रतिनिधियों का जयपुर दौरा (17–18 जनवरी)

17 और 18 जनवरी को 40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 संसदीय प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में प्रवास करेगा। इस दल में राष्ट्रमंडल देशों के विधायिकाओं के अध्यक्ष, विधायिका सदस्य तथा वरिष्ठ संसदीय अधिकारी शामिल होंगे। शनिवार सुबह जयपुर हवाई अड्डे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधि राज्य की संसदीय कार्य प्रणाली और संसदीय परंपराओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही, वे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे, जिससे शासन-आउटरीच को सांस्कृतिक कूटनीति और पर्यटन-परिचय के साथ जोड़ा जा सकेगा।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रमंडल संसदीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर में दो दिन (17–18 जनवरी) रहेगा।
- प्रतिनिधिमंडल में 40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 सदस्य शामिल हैं।
- शनिवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे।
- दौरे में राज्य की संसदीय कार्य प्रणाली और कार्य-परंपराओं का परिचय/अध्ययन शामिल रहेगा।
- पहले दिन प्रतिनिधि आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल का भ्रमण करेंगे।
- विरासत स्थलों के भ्रमण के बाद दोपहर में प्रतिनिधिमंडल कांस्टीट्यूशनल क्लब का दौरा करेगा।
- सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने तैयारियों की समीक्षा कर व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखने और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- प्रतिनिधिमंडल को संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं से परिचित कराने हेतु अध्ययनात्मक गतिविधियाँ आयोजित करना।
- दो दिवसीय कार्यक्रम में जयपुर की विरासत और सांस्कृतिक स्थलों का प्रदर्शन/परिचय कराना।
- अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से दौरे की लॉजिस्टिक्स और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना।

लाभ

- राजस्थान और राष्ट्रमंडल विधायिकाओं के बीच संस्थागत संवाद और संसदीय अनुभव-विनिमय को बढ़ावा।
- शासन-परिचय और सांस्कृतिक पर्यटन को साथ जोड़कर जयपुर की राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दृश्यता में वृद्धि।
- उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की सफल व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक क्षमता और समन्वय का प्रदर्शन।

निष्कर्ष

40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 संसदीय प्रतिनिधियों का जयपुर दौरा संसदीय अध्ययन के साथ-साथ विरासत-आउटरीच का अवसर है। संसदीय परंपराओं के अध्ययन को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के अभ्यास से जोड़कर यह कार्यक्रम राजस्थान की शासन-व्यवस्था और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों को रेखांकित करता है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गई तैयारी-समीक्षा यह भी दर्शाती है कि उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय दौरों के प्रबंधन में विभागीय समन्वय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

Q1. 17–18 जनवरी को जयपुर आने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं:

- a) 50 देशों के 100 प्रतिनिधि
- b) 40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 संसदीय प्रतिनिधि
- c) 35 राष्ट्रमंडल देशों के 140 प्रतिनिधि
- d) 40 देशों के 80 प्रतिनिधि

उत्तर: b

समाचार के अनुसार 17 और 18 जनवरी को 40 राष्ट्रमंडल देशों के 120 संसदीय प्रतिनिधि जयपुर आएँगे, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q2. जयपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रमंडल संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कौन करेंगे?

- a) राजस्थान के मुख्य सचिव
- b) राजस्थान के राज्यपाल
- c) राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

d) राजस्थान के मुख्यमंत्री

उत्तर: c

समाचार में बताया गया है कि शनिवार सुबह जयपुर हवाई अड्डे पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे, इसलिए विकल्प (c) सही है।

Q3. पहले दिन विरासत भ्रमण में प्रतिनिधिमंडल किन स्थलों पर जाएगा?

- a) नाहरगढ़ किला, जल महल, जंतर मंतर, बिरला मंदिर
- b) आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल
- c) आमेर किला, जंतर मंतर, जल महल, अल्बर्ट हॉल
- d) बिरला मंदिर, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ किला, हवा महल

उत्तर: b

कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल का भ्रमण होगा तथा बाद में कांस्टीट्यूशनल क्लब का दौरा किया जाएगा, इसलिए विकल्प (b) सही है।

The first Guava festival will be held in Sawai Madhopur; it will be inaugurated on 18 January (11 AM) and Lok Sabha Speaker Om Birla will be the chief guest.



The 263rd anniversary of Sawai Madhopur is being observed by Tiger Festival and Guava festival this year. The Agriculture and Horticulture Minister of Rajasthan Dr. Kirodi Lal Meena announced the first Guava Festival in India is being hosted at Sawai Madhopur and the festival is historic because of the efforts of boosting income

of farmers. Lok Sabha Speaker Om Birla will be the chief guest in the festival, which will be opened on 18 January at 11 AM. The event is not placed as a ceremonial role but as a platform to enable the farmers to get a better price realisation, access a technology and a market connection and provide Sawai Madhopur agricultural identity with a national presence.

Major attractions of the festival and its mission:-

- Guava Festival & Advanced Agriculture Technology Fair-2026 is an upcoming initiative to empower farmers as a measure that is futuristic.
- The guava of Sawai Madhopur has been identified to be a quality produce that has its demand in both national and international markets.
- The two-day programme will focus on bringing together knowledge, innovation and opportunities to farmers.
- The areas of focus are modern farming, smart farming, agricultural mechanisation, drone technology, high-tech horticulture, processing and value addition.
- Core institutional goal: establish a direct contact between farmers, scientists and traders in order to enhance results and decrease reliance on intermediaries.

Key data points (as stated)

- Guava planting in Sawai Madhopur: More than 15,000 hectares.
- Production per annum: about 4 lakh metric tonnes.
- Business value per year: 6700000-7000000.

What will be showcased

- Demonstration on various varieties of guava.
- Competitions on fruits and flowers.
- Contribution of 20+ interstate nurseries.

Around 200 stalls featuring:

- The farming tools and equipment.
- Horticulture technologies
- Organic and natural farming
- On-site experiments on livestock farming and dairy.
- Exhibition of value-added products made out of guava: juice, jelly, squash, pulp, barfi, chutney and pickle.

The governance and economic applicability in the case of RAS.

- Farmer income and agri-value chain: market access, agri-value chain, and price discovery.

- In the agricultural industry, technology includes mechanisation, drones, smart agriculture, high-tech horticulture.
- Rural entrepreneurship and exports Value addition and branding towards external markets.
- Institutional coordination: to lessen friction and enhance efficiency, there should be farmer-scientist discussion and buyer-seller forums.

Conclusion

The initiative will transform a robust local crop identity into a formal ecosystem of better prices, better technology and better markets, and aims to make a firm push towards making the district a future guava production and export centre by introducing the first Guava Festival in Sawai Madhopur and combining it with an enhanced level of agricultural technology.

MCQs (RAS Prelims pattern)

Q1. As stated in the news, the first Guava Festival in India is to be held therein:

- a) Ajmer
- b) Sawai Madhopur
- c) Kota
- d) Udaipur

Answer: b

Explanation: The report informs that the Guava festival, the first of its kind in India, is being organised in Sawai Madhopur.

Q2. Guava Festival will open on 18 January at 11 AM and will be attended by:

- a) Prime Minister of India
- b) Rajasthan Chief Minister.
- c) Lok Sabha Speaker Om Birla
- d) Governor of Rajasthan

Answer: c

Explanation: The programme will be launched on 18 January at 11 AM and Lok Sabha Speaker Om Birla will be the chief guest.

Q3. Which of the below sets is the correct one in terms of matching the key figures provided on the cultivation of guava in Sawai Madhopur?

- a) 5,000 hectares; 1 lakh metric tonnes; 1-2 billion 8.
- b) 10,000 hectares; 2 lakh metric tonnes; 3-4 billion.
- c) 15,000 and above, hectares; 4 lakh and above, metric tonnes; 6 0007000 billion.
- d) 20,000 and above hectares; 6 lakh and above metric tonnes; 10-12 billion rupees.

Answer: c

Explanation: The news states that there are 15, 000 and above hectares of guava planted, about 4 lakh metric tonnes of production, and 6-7 billion business worth every year.

भारत का पहला अमरुद महोत्सव सवाई माधोपुर में; उद्घाटन 18 जनवरी (सुबह 11 बजे), मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।

सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस इस वर्ष बाघ महोत्सव और अमरुद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि भारत में पहली बार अमरुद महोत्सव सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस महोत्सव का उद्घाटन 18 जनवरी को प्रातः 11 बजे होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहेंगे। यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, तकनीक तक पहुंच और बाजार से जोड़ने का एक मंच है, साथ ही सवाई माधोपुर की कृषि पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास भी है।

महोत्सव की प्रमुख विशेषताएँ और उद्देश्य

- अमरुद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला-2026 किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में दूरदर्शी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- सवाई माधोपुर के अमरुद को उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद बताया गया है, जिसकी मांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रही है।
- दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और अवसरों का समन्वय करना है।
- प्रमुख फोकस क्षेत्र: आधुनिक खेती, स्मार्ट फार्मिंग, कृषि यंत्रीकरण, ड्रोन तकनीक, हाई-टेक बागवानी, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन।

- मुख्य संस्थागत लक्ष्य: किसानों, वैज्ञानिकों और व्यापारियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर परिणाम बेहतर बनाना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना।

प्रमुख आंकड़े (जैसा बताया गया)

- सवाई माधोपुर में अमरुद की खेती: 15,000 हेक्टेयर से अधिक।
- वार्षिक उत्पादन: लगभग 4 लाख मीट्रिक टन।
- वार्षिक कारोबार मूल्य: 6–7 अरब रुपये।

क्या-क्या प्रदर्शित किया जाएगा

- अमरुद की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी।
- फल एवं फूल प्रतियोगिताएँ।
- विभिन्न राज्यों की 20+ नर्सरियों की भागीदारी।
- लगभग 200 स्टॉल्स, जिनमें:
 - कृषि उपकरण और यंत्र
 - उद्यानिकी तकनीक
 - जैविक एवं प्राकृतिक खेती
 - पशुपालन और डेयरी के लाइव डेमोस्ट्रेशन
- अमरुद से बनने वाले वैल्यू-एडेड उत्पादों की प्रदर्शनी: जूस, जैली, स्क्वेश, पल्प, बर्फी, चटनी और आचार।

RAS के लिए शासन एवं आर्थिक प्रासंगिकता

- किसान आय और कृषि मूल्य शृंखला: बाजार तक पहुंच, मूल्य-निर्धारण और बेहतर मूल्य प्राप्ति।
- कृषि में तकनीकी अपनाव: यंत्रीकरण, ड्रोन, स्मार्ट खेती, हाई-टेक बागवानी।
- ग्रामीण उद्यमिता और निर्यात: मूल्य संवर्धन और बाहरी बाजारों के लिए ब्रांडिंग।
- संस्थागत समन्वय: कृषक-वैज्ञानिक संवाद तथा क्रेता-विक्रेता मंचों के माध्यम से दक्षता बढ़ाना और घर्षण कम करना।

निष्कर्ष

सवाई माधोपुर में भारत के पहले अमरुद महोत्सव का आयोजन और इसे उन्नत कृषि तकनीकी मेले के साथ जोड़ना स्थानीय फसल पहचान को एक संगठित व्यवस्था में बदलने का प्रयास है, ताकि बेहतर मूल्य, बेहतर तकनीक और बेहतर बाजार सुनिश्चित किए जा सकें। यह पहल सवाई माधोपुर को भविष्य में अमरुद उत्पादन और निर्यात के संभावित केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में प्रस्तुत की गई है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स)

Q1. समाचार के अनुसार भारत का पहला अमरूद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है?

- a) अजमेर
- b) सवाई माधोपुर
- c) कोटा
- d) उदयपुर

उत्तर: b

समाचार के अनुसार भारत में पहली बार अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q2. अमरूद महोत्सव का उद्घाटन 18 जनवरी को प्रातः 11 बजे किसके मुख्य आतिथ्य में होगा?

- a) भारत के प्रधानमंत्री
- b) राजस्थान के मुख्यमंत्री
- c) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
- d) राजस्थान के राज्यपाल

उत्तर: c

समाचार में बताया गया है कि उद्घाटन 18 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए विकल्प (c) सही है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा सेट सवाई माधोपुर में अमरूद की खेती के आंकड़ों के सही संयोजन को दर्शाता है?

- a) 5,000 हेक्टेयर; 1 लाख मीट्रिक टन; 1–2 अरब रुपये
- b) 10,000 हेक्टेयर; 2 लाख मीट्रिक टन; 3–4 अरब रुपये
- c) 15,000+ हेक्टेयर; लगभग 4 लाख मीट्रिक टन; 6–7 अरब रुपये
- d) 20,000+ हेक्टेयर; लगभग 6 लाख मीट्रिक टन; 10–12 अरब रुपये

उत्तर: c

समाचार के अनुसार सवाई माधोपुर में 15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद की खेती होती है, वार्षिक उत्पादन लगभग 4 लाख मीट्रिक टन है और वार्षिक कारोबार 6–7 अरब रुपये बताया गया है, इसलिए विकल्प (c) सही है।

Rajasthan has introduced One District One Product Policy 2024 as an attempt to empower the industries at the district level.



To support local industries and provide sustained employment opportunities throughout the state, Rajasthan has adopted the One District One Product Policy 2024 to market various products of each district. This policy has seen the identification of products to all 41 districts in line with the state interest in inclusive economic development. The policy is supposed to promote entrepreneurship, market access by local producers and enhancing product quality in terms of technology adoption, branding and basic infrastructure provision. It also provides institutional and financial support in structure so that the entrepreneurs on the district level have a better chance to compete in large markets and develop a sustainable growth that depends on local identity.

Market characteristics of One District One Product Policy 2024.

- Introduces and markets district products in all the 41 districts.
- Promotes entrepreneurship and empowers the industries at the district level by providing systematic support.
- Enhances access to the market by the local manufacturers and helps them to be competitive.
- Ensures the adoption of technology, branding and quality improvement using infrastructure and services.

Provides capital subsidy:

- New micro enterprises: between 25 and 15 lakh.
- Small businesses: 15 percent of the available project cost, not more than 20 lakh.

Expenses National and international exhibitions with:

- Rent assistance and traveling allowance up to 2L.
- Favours the development of clusters by creation of Common Facility Centres (CFCs).

Covers quality certifications and costs associated with IPR:

- Up to 75%, maximum ₹3 lakh.

Has onboarding support on e-commerce platforms:

- Maximum up to 75, for two years, 1 lakh or less.

Encourages technological advancement:

- Maximum of 50 percent subsidy, to a limit of 5 lakh, of advanced technology/software by recognised national institutions.

Assists in cataloguing services and web-development of e-broker:

- Up to 60% support, maximum ₹75,000.

Objectives and benefits

Objectives

- Support local industries and products locally by encouraging local products.
- Empower improved market connection, use of technology, and branding of the local producers.
- Develop long term jobs through making district industries more competitive.

Benefits

- Enhances realisation of prices and access to markets of local products with systematic aid.
- Promotes the use of innovation and technology at the district level.
- Enhances development through cluster-based development through CFCs and exposure to exhibitions.
- Favors quality enhancement, certification, and IPR protection, enhancing the competitiveness.

Conclusion

One District One Product Policy 2024 is a systematic bundle of financial aid, innovation assistance, and market growth instruments to enhance business on a district level in Rajasthan. It also promotes sustainable economic development by empowering the local handicraft and entrepreneurs, as well as preserving the base of craft and cultural products in the state. In the long run, the policy framework is aligned in order to establish more powerful local-to-wider-market connectivity and increase opportunities in India and beyond.

MCQs (RAS Prelims pattern)

Q1. The primary goal of the One District One Product Policy of 2024 in the state of Rajasthan is to:

- a) Substitute district industry by large centralised industries.
- b) Spread products, district-based, build local industries, and develop sustainable employment.
- c) Micro-manage the entrepreneurship by limiting access of the market to local levels only.
- d) Limit to the urban industries, and ignore rural producers.

Answer: b

Reason: The policy is targeted at marketing the unique products of every district, developing local industries, and establishing sustainable employment in the entire state of Rajasthan.

Q2. The appropriate capital subsidy support according to the policy is:

- a) New micro enterprises: 15% to 20 lakh; Small enterprises: 25% to 15 lakh.
- b) New micro enterprises 25 per cent to 15 lakh; Small enterprises 15 per cent to 20 lakh.
- c) New micro enterprises: 50 to 750000 rupees; Small enterprises: 60 to 75000 rupees.
- d) New micro enterprises: 75 percent until 3 lakh INR; Small enterprises: 75 percent until 1 lakh INR/per year.

Answer: b

Explanation: The policy gives capital subsidy (no more than 25 percent (restricted to 15 lakh) on new micro enterprises and up to 15 percent (restricted to 20 lakh) on small enterprises on the qualifying cost of the project.

Q3. Which of the below best fits the reimbursement/support provisions in the policy?

- a) Quality certifications and IPR: 50 percent until 5 lakh; E-commerce onboarding: 60 percent up to 75000.
- b) Quality certifications and IPR: 75% up to 3 lakh rupee; Onboarding E-commerce: 75% up to 1 lakh rupee in the first two years.
- c) Quality certifications and IPR: 25 per cent up to 15 lakh; Travel support onboarding of e-commerce up to 2 lakh.
- d) Quality certifications and IPR: stall rent support unlimited; E-commerce onboarding: financial support unavailable.

Answer: b

Explanation: The policy covers quality certifications and IPR expenses up to 75 (maximum 3 lakh) and two years up to 75 (maximum 1 lakh/year) to facilitate the joining of e-commerce platforms.

राजस्थान ने जिला-स्तरीय उद्योगों को सशक्त बनाने हेतु “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” लागू की है।

स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने और पूरे राज्य में रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ने “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” लागू की है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों का विपणन और प्रोत्साहन किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत राज्य के सभी 41 जिलों के लिए उत्पादों की पहचान की गई है, जो समावेशी आर्थिक विकास के राज्य उद्देश्य के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादकों की बाजार तक पहुँच बढ़ाना और तकनीक अपनाने, ब्रांडिंग तथा बुनियादी ढांचे के जरिए उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही, यह नीति जिला स्तर के उद्यमियों को संरचित संस्थागत और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे बड़े बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें और स्थानीय पहचान पर आधारित सतत विकास को आगे बढ़ा सकें।

“एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” की प्रमुख विशेषताएँ

- सभी 41 जिलों में जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान और प्रचार-प्रसार।
- उद्यमिता को प्रोत्साहन और जिला-स्तरीय उद्योगों को व्यवस्थित सहायता के जरिए सशक्त बनाना।

- स्थानीय निर्माताओं की बाजार तक पहुँच बढ़ाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना।
- तकनीक अपनाव, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार के लिए अवसंरचना एवं सेवाओं का समर्थन।
- कैपिटल सब्सिडी:
 - नए सूक्ष्म उद्यम: 25% तक, अधिकतम ₹15 लाख।
 - छोटे उद्यम: योग्य परियोजना लागत पर 15% तक, अधिकतम ₹20 लाख।
- राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु सहायता:
 - स्टॉल किराया सहायता और ₹2 लाख तक यात्रा सहायता।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) की स्थापना के जरिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा।
- गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR से संबंधित खर्चों पर सहायता:
 - 75% तक, अधिकतम ₹3 लाख।
- ई-कॉर्मर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने हेतु ऑनबोर्डिंग सहायता:
 - दो वर्षों तक प्रति वर्ष 75% तक, अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष।
- तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन:
 - मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी/सॉफ्टवेयर खरीद पर 50% तक सब्सिडी, अधिकतम ₹5 लाख।
- कैटलॉगिंग सेवाएँ और ई-कॉर्मर्स वेबसाइट विकास हेतु सहायता:
 - 60% तक, अधिकतम ₹75,000।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर स्थानीय उद्योगों और जिला-विशिष्ट उत्पादों को समर्थन देना।
- स्थानीय उत्पादकों के लिए बाजार जोड़, तकनीक उपयोग और ब्रांडिंग को मजबूत करना।
- जिला उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर दीर्घकालिक रोजगार के अवसर विकसित करना।

लाभ

- व्यवस्थित सहायता के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की मूल्य प्राप्ति (price realisation) और बाजार पहुँच में सुधार।
- जिला स्तर पर नवाचार और तकनीकी अपनाव को बढ़ावा।
- CFCs और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर-आधारित विकास को मजबूती।

- गुणवत्ता सुधार, प्रमाणीकरण और IPR संरक्षण को समर्थन देकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

निष्कर्ष

“एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” राजस्थान में जिला स्तर पर व्यवसायों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता, नवाचार सहयोग और बाजार-विस्तार उपकरणों का एक व्यवस्थित पैकेज प्रस्तुत करती है। यह नीति स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाकर सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और राज्य की शिल्प व सांस्कृतिक उत्पाद-आधार को संरक्षित करने में भी योगदान देती है। दीर्घकाल में यह फ्रेमवर्क स्थानीय से बड़े बाजारों तक मजबूत जोड़ बनाकर भारत और उससे आगे अवसरों का विस्तार करने की दिशा में उन्मुख है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

Q1. राजस्थान में “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- जिला उद्योगों को हटाकर बड़े केंद्रीकृत उद्योगों को बढ़ावा देना
- जिला-आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना और स्थायी रोजगार विकसित करना
- उद्यमिता को नियंत्रित कर बाजार तक पहुँच केवल स्थानीय स्तर तक सीमित करना
- केवल शहरी उद्योगों पर ध्यान देकर ग्रामीण उत्पादकों को नजरअंदाज करना

उत्तर: b

यह नीति प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों के विपणन/प्रोत्साहन, स्थानीय उद्योगों के सुदृढ़ीकरण और राज्य भर में स्थायी रोजगार अवसर विकसित करने पर केंद्रित है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q2. नीति के अनुसार कैपिटल सब्सिडी का सही प्रावधान क्या है?

- नए सूक्ष्म उद्यम: 15% तक ₹20 लाख; छोटे उद्यम: 25% तक ₹15 लाख
- नए सूक्ष्म उद्यम: 25% तक ₹15 लाख; छोटे उद्यम: 15% तक ₹20 लाख
- नए सूक्ष्म उद्यम: ₹5 लाख तक ₹75,000; छोटे उद्यम: 60% तक ₹75,000
- नए सूक्ष्म उद्यम: 75% तक ₹3 लाख; छोटे उद्यम: 75% तक ₹1 लाख/वर्ष

उत्तर: b

नीति में नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए 25% तक (अधिकतम ₹15 लाख) और छोटे उद्यमों के लिए योग्य परियोजना लागत पर 15% तक (अधिकतम ₹20 लाख) कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q3. निम्न में से कौन-सा विकल्प नीति के पुनर्भरण/सहायता प्रावधानों का सही संयोजन दर्शाता है?

- गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 50% तक ₹5 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: 60% तक ₹75,000
- गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 75% तक ₹3 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: 2 वर्षों तक 75% तक ₹1 लाख/वर्ष
- गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 25% तक ₹15 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: ₹2 लाख तक यात्रा सहायता
- गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: केवल स्टॉल किराया सहायता; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: कोई वित्तीय सहायता नहीं

उत्तर: b

नीति के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र व IPR खर्चों पर 75% तक (अधिकतम ₹3 लाख) पुनर्भरण और

January 17, 2026

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो वर्षों तक प्रति वर्ष 75% तक (अधिकतम ₹1 लाख/वर्ष) सहायता दी जाती है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

RASonly